भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
31.07.2024 के
तारांकित प्रश्न सं. 128 का उत्तर

रेल लाइन बिछाने संबंधी सर्वेक्षण

***128. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ में महासमुंद से तुमगांव, पिथौरा, बसना, सरायपाली, सोहेला और बारगढ़ मार्ग की रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है/लिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्ष 2024-25 के दौरान सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

रेल लाइन बिछाने संबंधी सर्वेक्षण के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में श्रीमती रूपकुमारी चौधरी के तारांकित प्रश्न सं. 128 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

इसके पूर्व, तुमगांव, पटेवा, पिथौरा, सरायपल्ली होते हुए महासमुंद से बरगढ़ नई लाइन (180 कि.मी.) के निर्माण के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था। इस व्यवहार्यता अध्ययन में कम यातायात का अनुमान किया गया था।

अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए रायपुर से संबलपुर (270 किलोमीटर) तक एक नया अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है। इस मार्ग का संरेखण महासमुंद जिले से होकर गुजरता है।

बहरहाल, महासमुंद पहले ही टिटलागढ़ के रास्ते बरगढ़ से जुड़ा हुआ है और पिछले 2 वर्षों में रायपुर-महासमुंद-टिटलागढ़ और टिटलागढ़-बरगढ़-संबलपुर दोनों का दोहरीकरण कार्य भी पूरा कर लिया गया है।

एकीकृत योजना बनाने, संभार प्रणाली की दक्षता बढ़ाने तथा लोगों, माल और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही हेतु बाधाओं को दूर करने, पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों सहित औद्योगिक समूहों, बंदरगाहों, खदानों, बिजली संयंत्रों, कृषि क्षेत्रों से संपर्कता स्थापित करने के उद्देश्य से, विभिन्न आर्थिक ज़ोनों में मल्टीमोडाल संपर्कता के अनुरूप अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के तहत छत्तीसगढ़ में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले कुल 5223 किलोमीटर लम्बाई के 59 सर्वेक्षण कार्यों (25 नई लाइन, 34 दोहरीकरण) को शुरू किया गया है।

भारतीय रेल में रेल परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। रेल अवसंरचना परियोजनाएं चालू परियोजनाओं की देयताओं, निधियों की समग्र उपलब्धता

और प्रतिस्पर्धी मांगों के आधार पर लाभप्रदता, अंतिम छोर तक संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर शुरू की जाती हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 25 परियोजनाएं (08 नई लाइन और 17 दोहरीकरण) जिनकी कुल लंबाई 2,731 किलोमीटर और लागत 37,018 करोड़ रुपये है, योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिसमें से 882 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक, इन पर 14,919 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(i) 08 नई लाइन परियोजनाएं, जिनकी कुल लंबाई 1,358 किलोमीटर और लागत 20,414 करोड़ रुपये है, जिसमें से 184 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक, इन पर 6,154 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(ii) 17 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनकी कुल लंबाई 1,373 किलोमीटर और लागत 16,604 करोड़ रुपये है, जिसमें से 698 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक, इन पर 8,765 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

छत्तीसगढ़ में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आवंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	311 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष	-
2023-24	6008 करोड़ रुपए	19 गुना से अधिक
2024-25	6922 करोड़ रुपए	22 गुना से अधिक

छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की कमीशनिंग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में परिवर्तन
2009-14	32 किलोमीटर	6.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष	-
2014-24	999 किलोमीटर	99.9 किलोमीटर प्रतिवर्ष	लगभग 15.6%

*****